**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्‍चतर शिक्षा विभाग

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 2041

उत्‍तर देने की तारीख: 28 जुलाई, 2014

**अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए रूपरेखा**

**2041. श्री गुलाम रसूल** **बलियावीः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों की शिक्षा के लिए वर्तमान सरकार के पास क्या रूपरेखा है;

(ख) यह पूर्ववर्ती सरकार की रूपरेखा से कितनी भिन्न है;

(ग) क्या कोई लक्ष्य तय किए जाएंगे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्‍तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्री**

**(श्रीमती स्‍मृति ज़ूबिन इरानी)**

(क) से (ड.): अल्‍पसंख्‍यक समुदायों सहित छात्रों की शिक्षा एक अनवरत प्रक्रिया है और सरकार शिक्षा में अल्‍पसंख्‍यकों की सहभागिता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का इस मामले में दोहरा दृष्टिकोण है जिसमें अल्‍पसंख्‍यक बहुल जिलों में केन्‍द्रीय योजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है जैसे सर्व शिक्षा अभियान, राष्‍ट्रीय माध्‍यमिक शिक्षा अभियान, मध्‍याह्न भोजन योजना, शिक्षक-शिक्षा योजना, प्रौढ़ साक्षरता, जवाहर नवोदय विद्यालय योजना (जेएनवी), बालिका छात्रावासों मॉडल स्‍कूल योजना, मॉडल डिग्री कॉलेजों, महिला छात्रावासों और पॉलिटेक्निकों इत्‍यादि की स्‍थापना करना ताकि शिक्षा के सभी स्‍तरों पर अल्‍पसंख्‍यकों की सहभागिता में संवर्धन हो। साथ ही मदरसा आधुनिकीकरण योजनाएं, अल्‍पसंख्‍यक स्‍कूलों में अवसंरचना विकास, स्‍कूल और कॉलेज शिक्षा जारी रखने की दिशा में अल्‍पसंख्‍यक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति तथा मुक्‍त विद्यालय के उपक्रम अल्‍पसंख्‍यक छात्रों और अल्‍पसंख्‍यक संस्‍थाओं को लाभ पहुंचाने के लिए विशेष रूप से लक्षित हैं।

इस योजना के पैरामीटरों के अनुसार केन्‍द्र प्रायोजित योजनाओं में अल्‍पसंख्‍यकों के लक्ष्‍य शामिल किए गए हैं जबकि स्‍कूल शिक्षा विभाग, भारत सरकार के 2014-15 के बजट अनुमानों में मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए अतिरिक्‍त 100.00 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

\*\*\*\*\*